VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
15 SEP 2018

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1072)

Name of Candidate	Ravi Kumar Sihag		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	168117
Center	MN	Date	15/09/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Explain why it is important to urgently address the problem of poor land records and infirmity of land titles in India. Also discuss how this problem can be addressed. **(150 Words) 10**

व्याख्या कीजिए कि भारत में ख़राब भू-अभिलेखों एवं भूमि अधिकारों के सुदृढ़ नहीं होने की समस्या का तत्काल समाधान करना क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही, चर्चा कीजिए कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।

आजादी के 70 वर्ष बाद भी भारतीय कृषि की विसंगतियों का एक बड़ा कारण खराब भू-अभिलेखों व भूमि-अधिकारों में निहित है। भू-अभिलेखों के उचित आँकड़ों के अभाव में निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं -

(क) काश्तकारों, बँटाईदारों आदि वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता

(ख) सरकारी डेटा के अभाव में विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ जैसे सिंचाई आदि का पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं हो पाता है

(ग) किसानों के मध्य असमानता का बढ़ना

(घ) जहाँ एक ओर भूस्वामी अपनी जमीन को कब्जे के भय से लीज पर देने से डरते हैं वहीं दूसरी ओर काश्तकारों को भी अनिश्चित समय के कारण जमीन में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निवेश एवं सुधार करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता।

(ङ) सरकारी परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में बाधा।

समाधान पक्ष :- (i) मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को पारित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना ताकि भू-स्वामी व काश्तकारों को अधिकार प्राप्त हो सके (भूमि - राज्य सूची विषय)

(ii) अशोक दलवई समिति की सिफारिशानुसार तकनीक का प्रयोग कर भूमि अभिलेख व आंकड़ों का संग्रह कर विस्तृत डेटाबेस तैयार करना।

(iii) 'किसान' की परिभाषा को विस्तृत बनाकर इसमें बटाईदारों व काश्तकारों को शामिल करना।

(iv) भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी संशोधनों की चर्चा की जा सकती है। साथ ही भूमि अधिकार नीति के अनुरूप महिला अधिकारों को भी बढ़ावा देना।

इन उपायों से भू-अभिलेख व भूमि अधिकारों की समस्या का समाधान सुझाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. What are the special features of the infrastructure sector that make its financing a challenge? What measures have been taken to facilitate adequate amount of finance to this sector?

(150 Words) 10

अवसंरचना क्षेत्रक के वे विशेष लक्षण क्या हैं जो इसके वित्तीयन को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं? इस क्षेत्रक में वित्त की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय किए गए हैं।

भारत में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों की सूची के तहत इस क्षेत्रक को परिभाषित किया गया है जिसमें भौतिक अवसंरचना (सड़क, रेल, बिजली) एवं सामाजिक अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य) आदि आते हैं।

*विशेष लक्षण :- वित्तीयन में चुनौती

(i) प्रोजेक्ट के आकारों का बड़ा होना जैसे भारतमाला परियोजना पर अनुमानित व्यय 5.35 लाख करोड़ है।

(ii) लंबी कार्यावधी :- कई लंबे प्रोजेक्ट जैसे नदी जोड़ो परियोजना दशकों तक चलेगा।

(iii) वित्त की समस्या
- बैंकों में बढ़ता एन.पी.ए
- कॉर्पोरेट द्वि तुलन पत्र समस्या
- बाह्य उधारियों की सीमित प्रवृत्ति

(iv) अपर्याप्त सरकारी नीतियाँ
- पीपीपी मॉडल में कमियाँ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- निजी क्षेत्र को कम प्रोत्साहन

(v) लाभार्जन क्षमता कम :- इन परियोजनाओं पर निवेश का लाभ प्रतिशत उतना अधिक नहीं होता है।

ऊर्जा क्षेत्र में बैंकों का NPA 4 लाख करोड़ के लगभग है। अतः अधिक वित्त प्रोत्साहन का अभाव है।

उपाय :- (i) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का विकास

(ii) मसाला बॉण्ड जैसे बाह्य उधारी तंत्र।

(iii) राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश फंड (NIIF) जैसे फंडों के फंड का विकास

(iv) इन्विट्स व रीट्स जैसे वित्तीय बाजार नवाचार (INVeITS & ReITs)

(v) राष्ट्रीय विनिवेश फंड

(vi) अन्य वैकल्पिक निवेश फंड व अन्य देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड।

(vii) बीमा फंड आदि

इसके साथ-साथ निवेश की शर्तों को आसान बनाने के उपाय भी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Despite favourable circumstances, India's electronics manufacturing has been unable to respond to the rising demand. Discuss. What steps can be taken to address this situation? **(150 Words) 10**

अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बढ़ती मांग के प्रति अनुक्रिया करने में असमर्थ रहा है। चर्चा कीजिए। इस परिस्थिति को संबोधित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत मोबाइल फोन, उनके कलपुर्जे, चिप्स के डिजाइन, विनिर्माण, एसेंबलिंग जैसे उद्योग आते हैं -

भारत की क्षमता
(i) बड़ा मांग बाजार / (iv) चीनी श्रम का
(ii) कुशल श्रम शक्ति / महंगा होना
(iii) विकसित सेवा क्षेत्र /

कम क्षमता के पीछे कारण
(क) इन उद्योगों के विकास के लिये अनुकूल स्थितियाँ - (A) बड़ा निवेश
(B) कूलिंग अवसंरचना
(C) क्लस्टरों का विकास

भारत में वित्त की समस्या के साथ क्लस्टरों के विकास का भी बड़ा प्रश्न विद्यमान है। साथ ही रेयर अर्थ खनिजों का भी आयात हमें करना पड़ता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) विभिन्न देशों जैसे- जापान, द. कोरिया से किये गये 'मुक्त व्यापार समझौते' सस्ते निर्यात को बढ़ावा देते हैं।
(ग) चीनी विकसित उत्पादों का सस्ता होना।
(घ) सरकारी नीति में कम प्रोत्साहन

उठाये जाने वाले कदम :-
(क) सरकार को 'क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण' को बढ़ावा देना चाहिये।
(ख) बिजली व अन्य अवसंरचना पक्षों को संबोधित करना।
(ग) श्रम के कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
(घ) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रोत्साहनों को देना
(ङ) अर्द्धचालक वैफर्स आदि के निर्माण में FDI आदि को प्रोत्साहित करना।

इन समाधानों के साथ भारत चीनी व उत्पादों को पछाड़कर विश्व के 'विनिर्माण हब' के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Despite registering a high growth rate in the post-reform era, India continues to witness a high incidence of poverty. Explain this paradox and suggest ways to resolve it. **(150 Words) 10**

आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में उच्च संवृद्धि दर दर्ज करने के बावजूद, भारत लगातार निर्धनता की अति व्यापकता का साक्षी रहा है। इस विरोधाभास की व्याख्या कीजिए और इसका समाधान करने के उपाय सुझाइए।

आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में भारत की उपभोग वृद्धि, जी.डी.पी वृद्धि के आधे से भी कम रही है। चूंकि गरीबी मापन में उपभोग के आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है अतः इस विरोधाभास के निम्न कारण होंगे -

(क) असमानता में वृद्धि :- विकास का लाभ ऊँचे तबके पर पहुँचना। ऑक्सफैम रिपोर्ट-नुसार 2016 में भारत के शीर्ष 1% लोगों ने कुल कमाई का 73% प्राप्त किया।

(ख) गरीबी के दुष्चक्र से निकालने में सरकारी नीतियों की विफलता

(ग) गरीबी मापन के आँकड़ों की अनिश्चितता

(घ) गरीबी की परिभाषा की व्यापकता भी गरीबी के प्रतिशत में बदलाव ला सकती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ङ) अर्थव्यवस्था वृद्धि के अनुरूप कौशल विकास न होना एवं रोजगार सृजन की कमी का विद्यमान होना।

(च) असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखती है।

उपाय :-

(क) अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण के प्रयास होना चाहिये → कौशल विकास
→ शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
– स्वास्थ्य में सुधार किया जाये

(ख) 'बॉटम-अप एप्रोच' से योजना का क्रियान्वयन

(ग) पीस मील इंजीनियरिंग द्वारा गांवों तक लोगों की पहुँच बढ़ाना।

(घ) नई पीढ़ी के गरीबी मापन एवं मापन के मानक विकसित कर उसके हिसाब से कार्य-योजना बनाना।

अतः गरीबी रूपी बहुआयामी समस्या को बहुआयामी रणनीति द्वारा ही हल किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. In light of the argument that India has entered a regime of "permanent surpluses", discuss whether the time has come to remove agricultural commodities completely from Essential Commodities Act. **(150 Words) 10**

इस तर्क के आलोक में कि भारत "स्थायी अधिशेषों" के युग में प्रवेश कर गया है, चर्चा कीजिए कि क्या कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से पूर्णतया हटा देने का समय आ गया है।

2014 एवं 2015 के लगातार दो सूखों के बाद भी भारत में खाद्यान्नों की कमी न होना इसके 'अधिशेषों' की प्रकृति का उदाहरण पेश करता है। अतः भारत को ज़रूरत है कि अधिशेष के प्रभाव-स्वरूप मूल्यों की कमी की समस्या को हल करे।

'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' राज्य सरकारों को सशक्त करता है कि वह विशेष स्थिति में विभिन्न जिंसों के मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उसके भंडारण को नियंत्रित करे। इसके परिणाम स्वरूप -

किसान :- इसे अपने उत्पादों का पूर्ण मूल्य नहीं मिल पाता (उपभोक्ता मूल्य का केवल 25%)

• व्यापारी वर्ग भी अवसंरचना विकास के लिये हतोत्साहित होते हैं।

इसी सन्दर्भ में कुछ समय पहले नीति आयोग ने अति-उत्पादन की समस्या के निदान हेतु इस अधिनियम पर विचार कर इसे हटाने की सिफारिश की थी।

लाभ	हानि / चुनौती
• किसान को अपने उत्पादों का दाम मिलेगा	- भविष्य में कालाबाजारी बढ़ सकती है।
• अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन	- गरीब व्यक्तियों के लिये दामों में वृद्धि हो सकती है

अतः इस अधिनियम को पूर्णतः समाप्त करने की पूर्वशर्तें निम्न हैं -

(i) व्यापक निगरानी तंत्र विकसित किया जाये ताकि कालाबाजारी न हो।

(ii) सरकारी विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का 'समावेशन' सुनिश्चित किया जाये।

(iii) सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर पूर्ण चर्चा के उपरान्त ही निर्णय लिया जाये।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. The 1988 National Forest Policy (NFP) was visionary in its scope and ambition. However, there is a need for a new forest policy in the current context. Discuss. **(150 Words) 10**

1988 की राष्ट्रीय वन नीति (NFP) अपने विषय-क्षेत्र और लक्ष्य की दृष्टि से दूरदर्शी थी। हालांकि, वर्तमान संदर्भ में एक नवीन वन नीति की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

1988 की राष्ट्रीय व नीति का उद्देश्य देश के एक-तिहाई भाग को वनावरण के अधीन लाना था। इस नीति के प्रभावों पर यदि विचार करें तो -

- पिछले 30 वर्षों में वनावरण 19% से बढ़कर 21.54% हो गया है।
- संयुक्त वन प्रबंधन जैसी अवधारणाएँ।

किन्तु 30 वर्ष पुरानी नीति वर्तमान समय की कुछ आवश्यकताओं से तालमेल नहीं बैठा पाती जैसे -

(क) पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत को INDC लक्ष्य को पूरा करना (2030 तक 2.5-3 बिलियन टन कार्बन सिंक सृजन)

(ख) निजी एवं वाणिज्यिक उपयोग (जैसे टिंबर आदि) के वनों के उपयोग हेतु।

(ग) सामुदायिक भागीदारी एवं सामुदायिक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वन अधिकारों को वन प्रबंधन में हिस्सा देना

(घ) वन प्रबंधन में स्थानीय बुद्धिमता के प्रयोग हेतु।

(ङ.) वनों की परिभाषा व उद्देश्यों में समयानुसार भिन्नता हेतु।

इसी कारण से नई राष्ट्र वन नीति 2018 लाई गई है जिसका उद्देश्य वनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित कर वर्तमान व भावी पीढ़ी हेतु वनों की सततता सुनिश्चित करना। उपर्युक्त सभी कमियों को सुनिश्चित करने हेतु इस नई वन नीति की आवश्यकता असंदिग्ध है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. How does rapid urbanization increases the vulnerability to major disasters? Explaining with examples, suggest measures to develop disaster-resilient cities. **(150 Words) 10**

द्रुत शहरीकरण प्रमुख आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को कैसे बढ़ाता है। उदाहरणों के साथ व्याख्या करते हुए, आपदा-प्रत्यास्थ शहरों का विकास करने के उपाय सुझाइए।

भारत में तीव्र शहरीकरण के फलस्वरूप हुए अनियंत्रित पर्यावास एवं अन्य कारणों ने आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा दिया है। हालिया केरल बाढ़ इसका उदाहरण है -

कारण

(i) शहरी अनियंत्रित पर्यावास के कारण शहरी निकास मार्गों का अवरोधन।

(ii) शहरी निकास मार्ग के लंबवत अवसंरचना निर्माण।

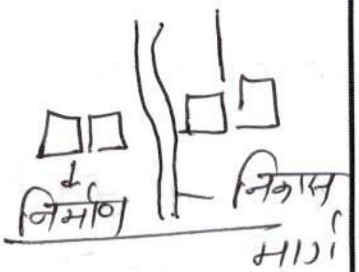

(iii) झुग्गी झोंपड़ियों का स्थान निचले ढलान की ओर होता है जो इनकी सुभेद्यता बढ़ा देता है।

(iv) शहरों के आकार में वृद्धि के कारण कंक्रीट सड़कों में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा का जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता जिससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) शहरी आगजनी की बढ़ती घटनाएँ क्योंकि उचित विद्युत फिटिंग न किया जाना।

(vi) अर्बन हीट आइलैंड जैसी अवधारणा के कारण बढ़ती प्रदूषण की समस्या।

सुझाव :-

(i) उचित शहरी योजना पर बल।

(ii) शहरी पर्यावास नीति एवं प्रवास नीति को शहरी विकास योजना से जोड़ा जाना।

(iii) 'बिल्ड बैक बैटर' एप्रोच के साथ आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (DRI) का निर्माण

(iv) झुग्गी पुनर्वास आदि कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये।

(v) शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना

(vi) प्रदूषण के लिये बहुआयामी एप्रोच का विकास करना।

इन सुझावों के साथ राष्ट्रीय आपदा कार्य योजना 2016 का उचित क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Explain DNA profiling and highlight its forensic application. Also discuss the significance of DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018 in this regard. **(150 Words) 10**

डीएनए प्रोफाइलिंग की व्याख्या कीजिए और इसके फॉरेंसिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018 के महत्व पर चर्चा कीजिए।

डी एन ए प्रोफाइलिंग एक रसायनिक परीक्षण होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के डीएन ए का प्रयोग कर उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। यह क्रियाविधि 'डीएन ए बहुरूपता' पर आधारित होती है।

अनुप्रयोग :- (i) कानून व्यवस्था, फॉरेंसिक में अपराधियों का पता लगाने में।
(ii) खोए हुए की तलाश करने में
(iii) विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय लाशों की पहचान करने में।
(iv) बच्चों के माता-पिता की पहचान करने में एवं ~~लावारिस~~ नाजायज संतानों के मुकदमों को सुलझाने में।

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक :- यह विधेयक आपराधिक कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु डी एन ए प्रौद्योगिकी के ~~महत्व~~ प्रयोग हेतु लाया गया है। इसमें एक राष्ट्रीय बोर्ड, प्रयोगशालाओं, डाटा बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

महत्व
(क) अपराधियों का पता लग पायेगा जिससे दोष-सिद्धि दर में वृद्धि होगी।
(ख) खोए हुए की तलाश व लाशों की पहचान में सहूलियत रहेगी।
(ग) इसमें व्यक्ति की सहमति का प्रावधान किया गया है (कुछ अपवादों सहित जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा) ताकि निजता की सुरक्षा हो सके।
(घ) डेटा के दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान किया गया है।

अतः समयानुसार विज्ञान-तकनीक का प्रयोग ~~क~~ आज की मांग है और यह बिल इसी परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. What is meant by the term Blue Water Capabilities? In this context, identify the key measures that have been undertaken to enhance the blue water capabilities of the Indian Navy. **(150 Words) 10**

ब्लू वाटर क्षमताएँ पद का क्या अर्थ है? इस प्रसंग में भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं का संवर्द्धन करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों की पहचान कीजिए।

ब्लू वाटर क्षमताएँ पद का अर्थ है कि किसी भी देश की नौसेना का अपने देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर जाकर विभिन्न अभियानों का अंजाम देने की क्षमता। ब्लू वाटर शब्द दूरस्थ समुद्री क्षेत्र को व्यक्त करता है।

भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर क्षमताओं से युक्त करने हेतु प्रमुख उपाय निम्न है -

(क) प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर 'आई एन एस विक्रमादित्य' - साथ ही स्वदेशी रूप से विकसित एक अन्य कैरियर का भी निर्माण किया जा रहा है

(ख) आई. एन. एस कलवरी जैसी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ।

(ग) आई. एन. एस. किलटन जैसे स्टील सबमरीन वारफेयर ~~शी~~ का विकास।

अन्य देशों से सहयोग

(क) मालाबार अभ्यास (अमेरिका भारत जापान)

(ख) विभिन्न देशों के साथ किये गये सैन्य समझौते (जैसे सिंगापुर के साथ)

(ग) अमेरिका के साथ किया गये लॉजिस्टिक आदान-प्रदान हेतु लेमोआ समझौता।

संस्थानिक स्तर पर

(क) रक्षा उत्पादन नीति 2018 का ड्राफ्ट बनाना जो स्वदेशी उत्पादन क्षमता का विकास करेगी।

(ख) रक्षा नियोजन समिति का निर्माण करना।

इस प्रकार भारत विभिन्न स्तरों पर प्रयास करके अपने आप को ब्लू वॉटर नेवी युक्त देश के रूप में स्थापित कर रहा है

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Identify the factors that make India vulnerable to drug trafficking? Also discuss the key steps taken to deal with it in our country. **(150 Words) 10**

उन कारकों की पहचान कीजिए जो भारत को ड्रग तस्करी के प्रति सुभेद्य बनाते हैं? साथ ही, हमारे देश में इससे निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए।

हाल के दिनों में भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में भारी इजाफा हुआ है जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं-

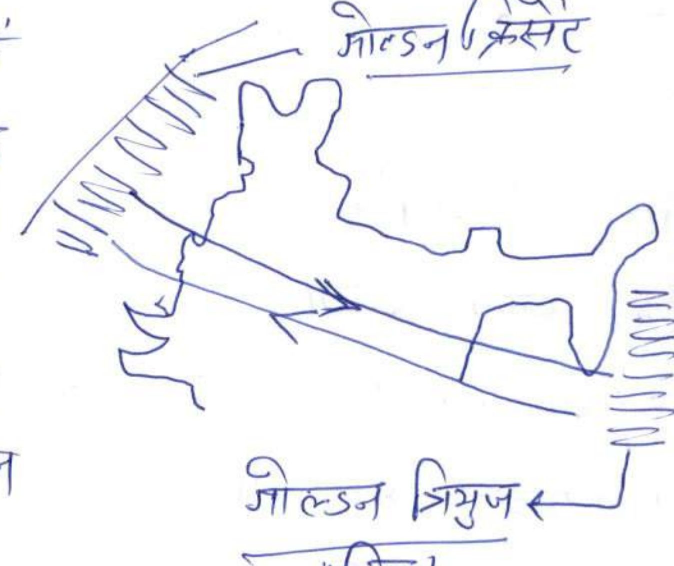

(क) भारत की भौगोलिक स्थिति (चित्र) इसे एक पारगमन गलियारे के रूप में स्थापित करती है।

(ख) कुछ धन लेकर सप्लाई करने वाले लोगों की बहुलता।

(ग) भारत का सीमा प्रबंधन दक्ष न होना। पंजाब सीमा पर सुरंगों में कपड़े की रस्सियों द्वारा तस्करी की खबरें आई हैं।

(घ) बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का प्रभाव

(घ) कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन
(ङ) राजनीतिक - तस्कर गठजोड़।

कदम :- (i) मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि की अवधि 2020 तक बढ़ा दी है।
(ii) स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एवं इनके व्यापार पर नियंत्रण हेतु अधिनियम 1988।
(iii) संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तस्करी के 1961, 1971 व 1988 के कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर करना।
(iv) अमेरिका, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल के साथ समझौते।
(v) मांग पक्ष :- (A) नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना।
(B) जागरूकता अभियान।

भारत को इन सभी उपायों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग भी बढ़ाना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. How do higher global crude oil prices affect the Indian economy? What steps can be taken to gradually insulate India from global oil price volatility in the long term? **(250 Words) 15**

कच्चे तेल की उच्च वैश्विक कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? दीर्घावधि में भारत को वैश्विक तेल की अस्थिर कीमतों से सुरक्षित करने के लिए उत्तरोत्तर कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

रुपये के मूल्य में आई हालिया गिरावट के पीछे उच्च तेल के मूल्यों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा हेतु तेल आयात पर निर्भर है अतः ~~भारत को~~ इनकी उच्च कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं।

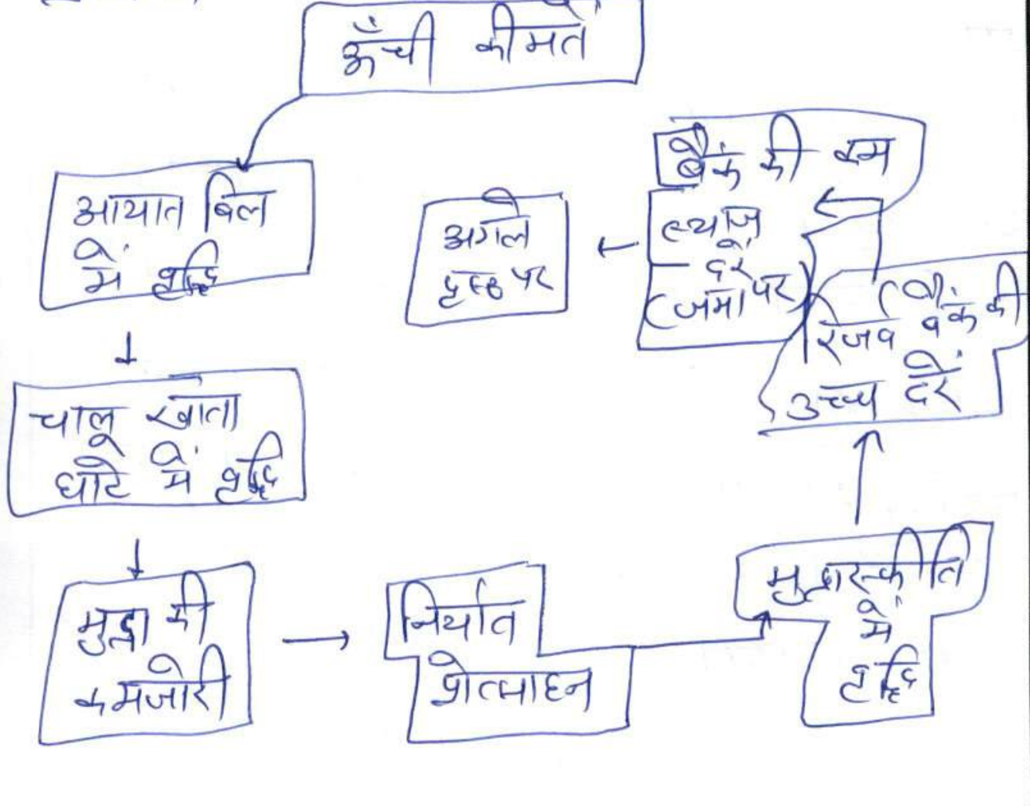

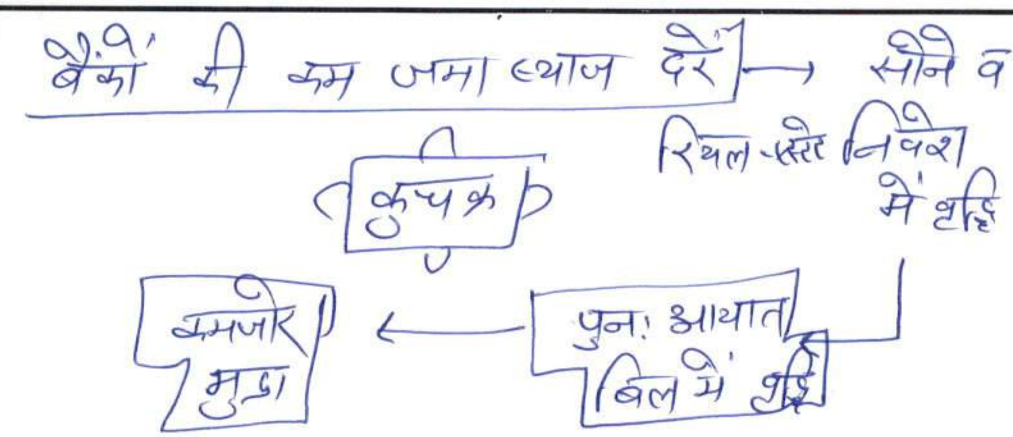

इस प्रकार कच्चे तेल की कीमतें एक कुचक्र को जन्म देती है जो हमारी समष्टिगत आर्थिक नीतियों पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

इस कुचक्र से लड़ने हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं -

(A) स्ट्रैटेजिक तेल भंडार :- ऐसे तेल भंडार अन्तर्राष्ट्रीय कीमत परिवर्तन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 'शॉक ऑब्जर्वर' की तरह काम करेंगे। अबु धाबी की कंपनी एडनॉक की सहायता से एक पर काम चल रहा है। अन्य की स्थापना हेतु विदेशी सहयोग आमंत्रित करना चाहिये।

(B) भारत के ऊर्जा समिश्र (फ्यूल बास्केट)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

में विविधता लाना :
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बल देना
- मेथेनॉल, जैव ईंधन आदि नवीन तकनीकों पर अनुसंधान बढ़ाना चाहिये

(c) ईंधन बचतकारी तकनीकों का विकास करना
- भारत VI मानकों का उचित क्रियान्वयन किया जाये

(d) फेम इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

(e) विकेन्द्रित ऊर्जा ग्रिडों का विकास कर 'गोबर धन' जैसी परियोजनाओं का उचित क्रियान्वयन।

(f) अविवेकपूर्ण ईंधन प्रयोग को उचित कर लगाकर हतोत्साहित किया जाये

(g) सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये

इन सभी उपायों से हम इस भावी खतरे की तीव्रता को कम कर सकते हैं साथ ही देश में विद्यमान संसाधनों व क्षमता का भी दोहन करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Critically discuss the role of private sector in skill development in India in recent years. In this context, what are the measures required to improve oversight as well as financing in the skill development sector?

(250 Words) 15

हाल के वर्षों में भारत में कौशल विकास में निजी क्षेत्रक की भूमिका की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, कौशल विकास क्षेत्रक में निरीक्षण और साथ ही वित्तीयन में सुधार के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक जहाँ जर्मनी में 75%, द० कोरिया में 96% श्रमिक कुशल हैं, वहीं भारत में केवल 4.69 % श्रमिक ही कुशल है। अतः इस मात्रा को बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी अनिवार्य है -

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The e-commerce sector has been booming in India for the last few years. Examine the need for its regulation in light of the recently proposed draft e-commerce policy. Further, identify the challenges that the sector is currently facing. **(250 Words) 15**

ई-कॉमर्स क्षेत्रक विगत कुछ वर्षों से भारत में तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में प्रस्तावित ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति के आलोक में इसके विनियमन की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्रक द्वारा वर्तमान में सामना की जाने वाली चुनौतियां की पहचान कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Explaining the importance, highlight the achievements of dairy sector in India. Examine whether over-production is the reason for the problems being faced by the dairy industry. Give some solutions to address the problems. **(250 Words) 15**

भारत में डेयरी क्षेत्र के महत्व की व्याख्या करते हुए, इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। परीक्षण कीजिए कि क्या अति-उत्पादन डेयरी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का कारण है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए।

भारत गत वर्ष 156 मिलियन मिट्रिक टन उत्पादन के साथ वैश्विक दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है। कुछ वर्षों में कहा जा रहा है कि भारतीय दुग्ध उद्योग अति उत्पादन की समता से ग्रसित है क्यों कि-

- दुग्ध के दामों में गिरावट का आना
- किसानों व उत्पादकों को कम लाभ प्राप्त होना आदि कारण इसके पक्ष में तर्क पेश करते हैं। किन्तु गहराई से देखें तो ये कारण उचित प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि-

(a) भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से कम है

(ख) दुग्ध के संबंध में लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ~~लोगों में~~ मांग सृजन की कमी विद्यमान है।

निर्यात पक्ष :- भारत अपने उत्पादन का 1% से भी कम निर्यात करता है जबकि न्यूजीलैंड जैसे देश अपने उत्पादन का 85% निर्यात कर रहे हैं।

- अन्य देशों द्वारा निर्यात प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग (खुरपका-मुंहपका रोग का कारण बताकर।
- प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों का कम प्रयोग।

उपाय :- (i) भारत को प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों पर व्यय बढ़ाना चाहिये जिससे
- दुग्ध के अति-उत्पादन की समस्या का भी समाधान होगा। (स्किम मिल्क पाउडर)
- उत्पादों में मूल्य वृद्धि होगी।
- भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी।

(ii) विभिन्न पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, भ्रूण स्थानान्तरण तकनीकों (ETT) पर निवेश

बढ़ाकर, चारा गुणवत्ता कार्यक्रमों पर व्यय बढ़ाना चाहिये।
(iii) 115 आंकाक्षापूर्ण जिलों में निहित कुपोषण की समस्या को दुग्ध की मांग सृजित कर समाप्त किया जा सकता है।

दुग्ध क्षेत्र का महत्व :-
(क) कृषि के अतिरिक्त आय का स्रोत।
(ख) कुपोषण से लड़ने में।
(ग) उचित मूल्य प्राप्ति (किसान को उपभोक्ता मूल्य का 75% प्राप्त होता है)

उपलब्धियाँ
(क) विश्व का सर्वोच्च उत्पादक देश।
(ख) सहकारी क्षेत्र में सफलतम (अमूल मॉडल का उदाहरण)
(ग) ~~देश को~~

15. There has been a focus on Textile and Apparels industry in India in recent years. Elaborate the potential of this industry and the challenges that lie in achieving it. What steps have been taken in this regard? **(250 Words) 15**

हाल के वर्षों में भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस उद्योग की संभावित क्षमता और उसे हासिल करने में निहित चुनौतियों की सविस्तार वर्णन कीजिए। इस संबंध में कौन-से कदम उठाए गए हैं?

आर्थिक समीक्षा 2016-17 एवं 2017-18 दोनों वस्त्र एवं परिधान उद्योग को देश के विकास एवं रोजगार सृजन में प्रमुख चालक के रूप में पेश किया गया है।

उद्योग की संभावित क्षमता

(क) देश में कपास उत्पादक क्षेत्रों के साथ साथ रेशम उत्पादन स्थलों की व्यापकता।

(ख) देश में कुशल श्रमिकों विशेषकर कपड़ा सिलाई, बुनाई करने वाली महिला श्रमिकों की उपलब्धता।

(ग) रोजगार के सन्दर्भ में इस क्षेत्र में 1 लाख रु का निवेश 24 लोगों को रोजगार (8 महिलाएं इनमें से) प्रदान करने की क्षमता रखता है। अन्य किसी भी

उद्योग की तुलना में यह अनुपात सर्वाधिक है
(घ) घर पर बैठकर कार्य करने की सुविधा का विद्यमान होना।
(ध) सरकार द्वारा 'रोजगार प्रोत्साहन योजना' जैसे कार्यक्रमों के द्वारा समर्थन।
(ङ) चीनी श्रमिकों की श्रमिक दर में वृद्धि होना।
चुनौतियाँ :- (क) संगठित कपड़ा उद्योग का अभाव।
(ख) महिलाओं के लिये उचित कौशल विकास का अभाव
(ग) बांग्लादेश जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा
(घ) 'यूरोपीय संघ' आदि देशों से मुक्त व्यापार समझौतों का अभाव निर्यात को हतोत्साहित करता है
(ङ) बिजली व सड़क आदि यातायात संबंधी अवसंरचना की समस्या।
उठाये जाने वाले कदम :- (क) GST लागू करना।
(क) केन्द्र सरकार एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा

कंपनियों व रोजगार प्रदाताओं द्वारा स्थायी श्रमिकों की भर्ती हेतु EPFO में सहयोग हेतु 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना।'

- कपड़ा क्षेत्र में तकनीकी विकास के प्रयास करना। 'राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान' के साथ जुड़ाव करना।
- टियर-2 व टियर-3 शहरों में कपड़ा उद्योगों की स्थापना कर वहाँ के सस्ते श्रम को रोजगार प्रदान करना।
- भारत में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के द्वारा इन उद्योगों के जुड़ाव पर कार्य किया जा रहा है।
- भारत द्वारा विभिन्न पश्चिमी देशों के साथ 'मुक्त व्यापार समझौतों' पर बल दिया जा रहा है।

इस प्रकार इन प्रयासों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में रोजगार चालक के रूप में वस्त्र क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। एवं परिधान क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। सरकार को चाहिये की एक नीति लाकर संपूर्ण क्षेत्र को एक साथ कवर किया जाये।

16. How do transportation corridors in biodiversity rich areas impact the wildlife? Examine the current policy framework in this regard. Also, suggest measures to minimise the negative effects while balancing the need for development. **(250 Words) 15**

जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में परिवहन गलियारे वन्य-जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इस संबंध में वर्तमान नीतिगत ढांचे का परीक्षण कीजिए। साथ ही, विकास की आवश्यकता को संतुलित करते समय इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वन्यजीवों के अबाध विचरण हेतु संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। विकास प्रक्रिया में विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे सड़क निर्माण के कारण इन वन्य-जीवों पर निम्न प्रभाव पड़ता है।

(क) मानव-पशु संघर्ष :- पशुओं के प्राकृतिक क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण उनका प्राकृतिक पर्यावास छिन जाता है और वे अपने आवास से बाहर जाने लगते हैं।

(ख) घटता जीन पूल :- किसी भी वन के मध्य से सड़क निकलने पर वन्य जीवों का दूसरी ओर विचरण कठिन हो जाता है जिससे वे केवल इसी ओर ही प्रजनन कर पाते हैं, जिससे जीन

स्थल में कमी आती है तथा इसी के कारण उनकी अनुकूलन क्षमता भी प्रभावित होती है।
(ग) वाहनों की टक्कर से पशुओं की मृत्यु।
(घ) वाहनों के शोर, प्रदूषण आदि वन्यजीवों के व्यवहार एवं प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

वर्तमान नीतिगत ढाँचा :- वर्तमान नीतिगत ढाँचे के अनुसार विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि में विभिन्न निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ-साथ सघन वन क्षेत्रों व इन नेशनल पार्कों के कोर क्षेत्रों में से नये सड़क निर्माण पर प्रतिबंध लागू है। हाँ, पहले से बनी हुई सड़क की चौड़ाई में वृद्धि की जा सकती है।

उपाय :- (i) ~~क्षत्रिय~~ परिवहन मंत्री का हालिया

सुझाव है कि सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि वन्यजीवों का विचरण बाधित न हो, इस हेतु अंडरग्राउंड या फ्लाइओवर का प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) वन्यजीव विविधता युक्त क्षेत्रों का विभाजन विभिन्न श्रेणियों में कर केवल बाहरी श्रेणियों में ही सड़क का निर्माण किया जाये।

(ग) किसी भी परियोजना को शुरू करते समय उसका सम्पूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किया जाये।

(घ) स्थानीय लोगों की भागीदारी को मजबूत कर उनके परामर्शानुसार भी कार्य करना बेहतर होगा।

विकास व पर्यावरण के द्वन्द्व में हमें ऐसा विकास चाहिये जो पर्यावरणीय पक्ष को अपने अंदर समाहित करें, न कि पर्यावरण की कीमत पर विकास किया जाय।

17. The potential of technology to aid farmers in increasing productivity as well reducing susceptibility to climate change remains underutilized. Identify the reasons for the same and suggest measures to improve technological penetration in agriculture. **(250 Words) 15**

उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करने हेतु किसानों की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पाया है। इसके कारणों की पहचान कीजिए और कृषि में प्रौद्योगिकी प्रसार में सुधार हेतु उपाय सुझाइए।

आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह ज़रूरी एवं क्षम्य हो गया है कि किसानों की दशा सुधार हेतु विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों की मदद से उनका उद्धार किया जाये।

पूर्ण दोहन न हो पाने के कारण

(क) अवसंरचना पक्ष
- इंटरनेट की पहुँच नहीं।
- किसानों की क्रय क्षमता उन्हें विभिन्न उपकरणों, फार्म मशीनों, हार्वेस्टर, इंटरनेट तक पहुँच नहीं होने देती।

(ख)- भाषा पक्ष :- किसानों को विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप उनकी भाषा में नहीं मिल पाते हैं।

(ग) अनुसंधान पक्ष :- अभी विभिन्न जलवायु

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रदेशों के अनुरूप अनुकूलित प्रौद्योगिकियों का विकास भी नहीं हो पाया है अर्थात पंजाब हरियाणा बनाम पूर्वी राज्यों का मुद्दा।

(घ) क्रियान्वयन पक्ष :- सरकारी प्रयासों की शिथिलता भी एक बड़ा मुद्दा है।

(ङ.) समावेशन का मुद्दा :- अभी भी प्रौद्योगिकी बड़े किसानों के पास है, छोटे किसानों तक उनकी पहुँच नहीं हो पाई है।

(च) एर्गोनोमिकली डिजाइन किये हुए उपकरणों का अभाव।

सुधार के उपाय :- (i) भारत का कृषि अनुसंधान व्यय कृषि जी. डी. पी. के 1% से भी कम है। सरकार को चाहिये कि बीज से बाजार तक समस्त क्रियाकलापों में अनुसंधान को बढ़ावा दे।

(ii) लैब टू इंडस्ट्री टू फॉर्म एप्रोच से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ आर्थिक रूप से मितव्ययी प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाये।
(iii) फॉर्म मशीनीकरण हेतु पूलिंग सिस्टम, किराये पर उपकरण जैसे प्रावधान किये जा सकते हैं।
(iv) आई. सी. टी. के विकास हेतु इंटरनेट पहुँच में विस्तार कर क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश, ऑडियो के द्वारा किसान जागरूकता में वृद्धि करना।
(v) छोटे किसानों के लिये उसी अनुपात में ट्रैक्टर आदि यंत्रों का विकास करना।
(vi) कृषि में बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि अत्याधुनिक प्रयोगों, ड्रोन के प्रयोग द्वारा सेंगसारी कृषि आदि अनुप्रयोगों में भी वृद्धि की जा सकती है।

अतः इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए किसानों को तकनीक की मदद से आगे बढ़ाया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What is Intelligent Transportation System (ITS)? Explaining the need of ITS in India, identify the challenges in deploying it. **(250 Words) 15**

कुशल परिवहन व्यवस्था (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम: ITS) क्या है? भारत में ITS की आवश्यकता की व्याख्या करते हुए, इसके परिनियोजन में आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए।

कुशल परिवहन व्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी परिवहन व्यवस्था जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है, साथ ही इसमें विभिन्न समस्याओं के स्वत: निराकरण की क्षमता विद्यमान होती है जैसे ट्रैफिक जाम की स्थिति में बत्तियों के समय का संयोजन, वैकल्पिक मार्ग सुझाना आदि।

भारत के सन्दर्भ में शहरों में विद्यमान भीड़, ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं के खतरों को कम करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है।

निजी वाहनों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण लगाने हेतु एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु भी यह व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है।

→ शहरी लोगों को परिवहन की लागत व समय को कम करने में भी इस प्रकार की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।
→ शहरों में विद्यमान प्रदूषण की समस्या से लड़ने में भी सहायक व्यवस्था।

परियोजना की चुनौतियाँ

(क) तकनीकी पक्ष :- अभी तक भारत में इस प्रकार की तकनीकों का अभाव है जो पूरे ~~यात~~ यातायात तंत्र को संभाल सके।

(ख) अवसंरचनात्मक पक्ष :- इस व्यवस्था के विकास के लिये अनेक प्रकार के यंत्रों जैसे स्मार्ट सेंसर, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर, सी.सी.टी.वी., कम्प्यूटर अवसंरचना की आवश्यकता होगी।

(ग) कुशल मानव संसाधनों की कमी, जो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस व्यवस्था को संचालित करने के लिये आवश्यक होंगे।

(घ) परिवहन साधनों को भी वाहनीयरूप में संशोधित करने की ज़रूरत पड़ेगी जो एक अन्य लागत का मुद्दा है।

(ङ) क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व राजकोषीय दबाव के मुद्दे।

अतः यह प्रौद्योगिकी एवं व्यवस्था तो अपने आप में अत्यन्त उत्तम है परन्तु हालिया चुनौतियों को देखते हुए भारत को चाहिये कि -

- अनुसंधान व विकास पर बल दे।
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे।
- उपयुक्त मानव संसाधन का विकास करे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Explain the concept and significance of Data Localisation. Also discuss its limitations in strengthening law enforcement efforts in the context of Srikrishna Committee report and the draft Personal Data Protection Bill, 2018. **(250 Words) 15**

डेटा लोकलाइजेशन की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। साथ ही, श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट और ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 के संदर्भ में कानून प्रवर्तन प्रयासों को सुदृढ़ करने में इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।

डेटा लोकलाइजेशन की अवधारणा से तात्पर्य है कि देश में जो भी डाटा उत्पन्न हो रहा है, इसकी स्टोरेज देश की सीमाओं के भीतर ही की जाये। अभी हालिया समय में भारत में गुगल, फेसबुक आदि कंपनियों के डेटा स्टोरेज स्थल भारत में नहीं है बल्कि भारत के बाहर स्थित है।

महत्व :-

(i) किसी भी ~~पर्सनल~~ व्यक्तिगत डाटा का दुरूपयोग रूकता है क्योंकि बाहरी जगहों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता।

(ii) डेटा प्रोसेसिंग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी, रुचियों की जानकारी लेना, उसकी पसंद-नापसंद के साथ-साथ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उसके लैंगिक रुझानों पर भी नजर रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

(iii) स्थानीय डेटा होने पर दुरुपयोग की दशा में दंड के प्रावधान किये जा सकते हैं।

(iv) भारत सरकार द्वारा जनता के कल्याण कार्यों - स्वास्थ्य, योजनाओं के ~~क्रियान्वि~~ क्रियान्वयन आदि में डाटा का प्रयोग किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What is the link between illegal immigration and national security? In this context, critically discuss the exercise of creating a National Register of Citizens in Assam. **(250 Words) 15**

अवैध आप्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य क्या संबंध है? इस संदर्भ में, असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने की क़वायद की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

अवैध प्रवासन से तात्पर्य है बिना अन्य देश की मंजूरी के किया गया प्रवासन या बिना जरूरी कागजातों (या फर्जी कागजातों) के किया गया प्रवासन या निश्चित व अनुमेय अवधि से अधिक समय तक किया गया प्रवासन।

हालिया रोहिंग्याओं का मुद्दा हो या असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा पर विद्यमान खतरों के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि-

(क) ये अवैध प्रवासी देश की जनांकिकीय संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं (उदा० त्रिपुरा) जिससे स्थानीय निवासियों में पहचान का संकट उत्पन्न हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सकता है। इसके साथ ही वे विरोध पर भी उतारू हो सकते हैं जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का विद्रोह।

(ख) विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है कि रोहिंग्याओं को विभिन्न राष्ट्रविरोधी तत्वों तत्वों द्वारा विद्रोही गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) स्थानीय निवासियों व प्रवासियों का टकराव भी अनिवार्य हिंसा को जन्म दे सकता है। ऐसी स्थितियाँ अलगाववादको जन्म देती है।

इस सन्दर्भ में असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर के संबंध में विवेचन किया जाना उपयुक्त होगा

लाभ	चुनौतियाँ
- अवैध शरणार्थियों पर लगाम लगेगी - देश के नागरिकों जैसे असम,	- वापिस भेजने की कोई क्रियाविधि नहीं बनाई गई है - अपवर्जनात्मक व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मेघालय त्रिपुरा के हित में	बहुत्यागिता की त्रुटियाँ रह सकती है। देश के कई नागरिक अपने ही देश में अजनबी बन सकते हैं
- शरणार्थियों द्वारा चलाई जा रही गैर-राष्ट्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगेगी।	- बांग्लादेश के साथ कोई समझौता नहीं है।
- 1985 के असम समझौते के अनुरूप	- अनावश्यक हिंसा को जन्म देगा।
	- राष्ट्रीय नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में।

इस प्रकार सरकार को चाहिये की सभी हितधारकों को विश्वास में लेते हुए बांग्लादेश के साथ समझौता कर इस प्रकार की योजना को अंजाम दे। कहीं ऐसा न हो कि यह रजिस्टर ही राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने एक नया खतरा पैदा कर दे।